International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 10 Issue 4, July-August, 2022, Impact Factor: 7.326

भारत में कृषि उत्पादकता; वृद्धि एवं सुधार

मनोज कुमार[1], धर्मेन्द्र कुमार भारती[2]

[1]शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान अध्ययन पीठ, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ 226025
[2]शोधार्थी, भूगोल विभाग, बयालसी पी0जी0 कालेज, वी0बी0एस0 पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

शोध सारांश (ABSTRACT)

अगर हम भारत में कृषि उत्पादकता की स्थिति की बात करें तो 1950 के दशक में जी0डी0पी0 में कृषि क्षेत्र का योगदान जहां 50 प्रतिशत था, वहीं 2015–16 में यह गिरकर 15.4 प्रतिशत रह गया (स्थिर मूल्यों पर) अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। और देश गेहूं, चावल, दाल, गन्ने और कपास जैसी फसलों के मुख्य उत्पादकों में से एक है। लेकिन किसी–किसी वर्ष में यह कृषि उत्पादकता घटती हुई पायी गयी है जो कि एक देश के लिए चिन्ता का विषय है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 10.07 करोड़ परिवार खेती पर निर्भर है। यह संख्या देश के कुल परिवारों का 48 फीसदी है (नाबार्ड, 2020)। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ किसानों के हित के लिए भारत सरकार किसानों की आय की दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधारभूत और संरचना के विकास पर बल दे रहे हैं अगर वर्तमान वृत्तीय वर्ष की बात करें सरकार ने किसानों को लागत मूल्य की डेढ़ गुना कीमत प्रदान करने के लिए खरीफ के फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में भारी वृद्धि कर दी है और किसान मानधन योजना 2019 में किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से लायी गयी है। जिससे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 6000 रूपये प्रदान किया जाता है और समय पर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि संस्थानों द्वारा उपाय सुझाये जाते हैं।

- ग्रामीण श्रम शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के लिए सामुदायिक विकास योजनाओं को लागू करना
- आधुनिक उपकरण उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई आदि का प्रयोग करके कृषि का स्थायी विकास करना।
- मुख्य शब्द; कृषि उत्पादता, जी0डी0पी0, नाबार्ड, किसान मानधन योजना, आत्मनिर्भर।

परिचय (INTRODUCTION)

भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी 54 से 60% ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर आधारित है। उनका जीवन यापन कृषि से ही चलता है। जी0डी0पी0 में कृषि का योगदान दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और वर्तमान समय में कृषि के जी0डी0पी0 17.5% योगदान है (भारतीय अर्थव्यवस्था 2020)। जो देश में कृषि के विकास के लिहाज से सही नहीं है और आने वाले समय में खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। जिससे भूखमरी एवं बेरोजगारी संकट उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अभी से ही देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र को बढ़ाना होगा और कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है जबकि औद्योगिक एवं सेवाक्षेत्र का विकास हो रहा है। इससे देश असमानता की स्थिति देखने को मिल रही है (भूखमरी सूचकांक, 2020)।

कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलु उत्पादन में लगभग 14% योगदान है लेकिन लगातार हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रहा है। 1950 के दशक में हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 53% होता था जो वर्तमान में करीब 14% रह गया है। देश में निर्यात के क्षेत्र में कृषि का 10% हिस्सा है। देश की 1.26 अरब आबादी की खाद्य सुरक्षा कृषि पर आधारित है। पिछले पॉच दशकों से आन्तरिक और बाहरी कारणों से समय–समय पर सरकार कृषि नीति में बदलाव करती रही। कृषि नीतियों को आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष में विभाजित किया जा सकता है। आपूर्ति पक्ष की बात की जाए तो इसमें भूमि सुधार भूमि उपयोग–कृषि विकास–नई प्रोद्योगिकी सिंचाई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सर्वाधिक निवेश वितरण प्रणाली का ठीक संचालन इत्यादि आता है। कृषि के लिए बनाई गई नीतियॉ सरकार के बजट को प्रभावित करती है। सरकार की औद्योगिक नीतियों में भी कृषि क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रावधान रखे जाते है। हरित क्रान्ति से पहले 1964–65 की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 2.7% की वार्षिक औसत वृद्धि हुई। इस अवधि में भूमि सुधार नीति और सिंचाई के विकास की दिशा में जोर दिया गया। हरित क्रान्ति के समय 1960 से 1997 के दशकों में वर्ष–1965–66 से 1975–76 की अवधि में कृषि क्षेत्र 3.3% की वृद्धि हुई और वर्ष

1976–77 से 1991–92 के दौरान कृषि क्षेत्र में 3.1% की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान सरकार की ओर से पर्याप्त नीति और पैकेज में इन उपजों को शामिल किया गया (कृषि वार्षिक रिपोर्ट– 2018)।

कृषि को मजबूत बनाने के लिए गेहूँ और चावल की उन्नत किस्मों का उपयोग कृषि से सम्बन्धित अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देना।

कृषि उपज को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों को प्रयोग को बढ़ावा देना।

उद्देश्य (OBJECTIVE)

1. भारत में कृषि उत्पादन अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय विश्लेषण करना।
2. भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि दर ज्ञात करना।

प्रविधि (METHODOLOGY)

यह शोध पेपर द्वितीय आंकड़ो पर आधारित है। जिसमें आंकड़ो का संग्रहण सरकारी, गैर–सरकारी, समाचार पत्रों, एजेन्सीयों, शोधपत्रों, किताबों, शोध वेबसाइट से आदि से लिया गया है और इस पेपर में सारणी दण्डा आरेख, ग्राफ आदि के माध्यम से इस शोध पत्र में बेहतर तरीके से कृषि उत्पादकता से सम्बन्धित आंकड़ो को सरल एवं सहज तरीकों से समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें साधारण सूत्रों का प्रयोग किया गया।

1.4 भारत में कृषि उत्पादकता की स्थिति; एक विश्लेषण (Status of Agricultural Productivity in India an Analysis)

भारत के पास चीन की तुलना में आर्थिक कृषि योग्य भूमि, कुल सिचिंत क्षेत्र तथा सकल बुआई क्षेत्र है। इसके बावजूद भारत चीन से कृषि उत्पादन के मामले में काफी पीछे है।

टेबलः 1 भारत चीन तुलना (कृषि क्षेत्र)

	चीन	भारत
कृषि योग्य भूमि	120 मिलियन हेक्टेयर	156 मिलियन हेक्टेयर
कुल सिंचित क्षेत्र	41 प्रतिशत	48 प्रतिशत
सकल बुआई क्षेत्र	166 मिलियन हे0	198 मिलियन हेक्टेयर
कृषि उत्पादन (कीमतें डालर में)	1367 बिलियन डॉलर	407 बिलियन डॉलर

स्रोतः इण्डियन एक्सप्रेस, 2019

उपरोक्त आंकड़ो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चीन ने भारत की तुलना में कृषि उत्पादकता में अधिक प्रगति की है। चीन में बढ़ते उत्पादन के लिए निम्नलिखित तीन कारक महत्वपूर्ण है जिससे भारत को सीख लेना चाहिए।

- कृषि सम्बन्धित नवाचार, अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश।
- कृषि बाजारों में सुधार के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ प्रदान करना।
- प्रत्यक्ष आय सहायता योजना (Direct Income Support Scheme)

❖ **कृषि संबधी नवाचार, अनुसंधान एवं विकास (Research & Development)**

- चीन द्वारा कृषि ज्ञान तथा नवाचार प्रणाली (Agriculture Knowledge and Innovation System- AKIS), जो कृषि सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकास के लिए जिम्मेदार है, के लिए वर्ष 2018–19 में 7.8 बिलियन डॉलर का निवेश किया गया, इसके विपरीत भारत ने इस क्षेत्र में मात्र 1.4 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
- कृषि संबधी अनुसंधान एवं शिक्षा (Agriculture Reseach & Education: Agri- R&E), पर होने वाले निवेश का सकल घरेलु उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP), पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस विषय पर हुए एक शोध के माध्यम से पता चला कि यदि हम Agri- R&E पर 1 रूपए का निवेश करते हैं तो कृषि GDP में 11.2 रूपए की वृद्धि होती है। यदि हम Agri- R&E पर 10 लाख का रूपए का निवेश करते हैं तो इससे 328 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है।
- चीन अपने कृषि–सकल मूल्य वर्धन (Agri- Gross Value Added) का 0.35 प्रतिशत Agri- R&E पर खर्च करता है जबकि भारत में यह खर्च 0.8 प्रतिशत है।
- R&D पर किये गए उच्च निवेश से निर्मित बीजों के लिये अधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। वर्ष 2016 में चीन में उर्वरक की खपत 503किग्रा0 प्रति हेक्टेयर थी, जबकि भारत के लिए यह खपत उसी वर्ष 166किग्रा0 प्रति हेक्टेयर की थी।

- अतः कृषि संबधी उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत को Agri- R&E पर निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

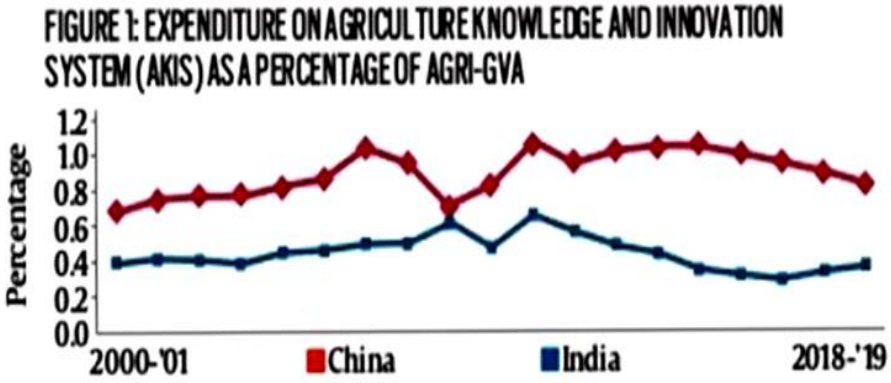

Source Estimated From World Bank data and OECD database

❖ कृषि बाजारों में सुधार के माध्यम से किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करना

- चीन, उत्पादक सहायता अनुमान (Producer Support Estimates- PSEs) द्वारा किसानों को प्रोत
- साहन राशि प्रदान करता है। इस मामले में चीन की स्थिति भारत से बेहतर है।
- PSE संकल्पना विश्व के उन 52 देशों द्वारा अपनाई गयी है जिनका विश्व के कुल कृषि उत्पादन में तीन– चौथाई का योगदान है। इसके तहत कृषि उपज से प्राप्त उस निर्गत मूल्य (Output Price) की गणना की जाती है जो कि किसान को मुक्त व्यापार की स्थिति में प्राप्त होती है। इससे किसानों द्वारा प्राप्त की गयी लागत सब्सिडी(Input Subsidy) को भी शामिल किया जाता है।
- चीन के किसानों के लिए PSE, उनके सकल फार्म प्राप्तियों (Gross Farm Receipts) के तीन वर्षो के औसत(Triennium Average Ending- TE) का 2018–19 में 15.3 प्रतिशत था। वहीं भारतीय किसानों के परिप्रेक्ष्य में इसी अवधि के दौरान 5.7 प्रतिशत था। इसका अर्थ यह है कि भारत का किसान, उसे प्राप्त होने वाले सब्सिडी से अधिक कर देता है।
- निगेटिव PSE का अर्थ है कि भारतीय किसानों को प्रतिबंधित बाजार तथा व्यापार नीतियों के कारण उनकी उपज की सही कीमत प्राप्त नहीं होती है जो उन्हें मुक्त बाजार की परिस्थितियों में प्राप्ति होती है।
- कृषि बाजार से सम्बन्धित इन कमियों को दूर करने के लिए भारत को वृहद पैमाने पर कृषि उत्पाद बाजार समिति (Agricultureal Poduce Market Committee- APMC) तथा अत्याश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) में सुधार करने की आवश्यकता है।

❖ प्रत्यक्ष आय सहायता योजना (Dirtect Income Support Scheme)

- चीन ने अपनी कई महत्वपूर्ण लागत सब्सिडियों को एक अलग योजना में समायोजित कर दिया है। जिसके तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रत्यक्ष भुगतान किया जाता है तथा फसल उगाने में हुई कुल लागत को बाजार मूल्यों के आधार पर तय किया जाता है। उस क्षेत्र में चीन ने वर्ष 2018–19 के दौरान 20.7 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
- वहीं भारत ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhanmantri Kishan Samman Nidhi: PM-KISAN) योजना के तहत प्रत्यक्ष आय सहायता में मात्र 3 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
- इसके विपरीत उर्वरक, विद्युत, सिंचाई, बीमा तथा ऋणों पर दी जाने वाली सब्सिडी पर 27 बिलियन डॉलर का निवेश किया। इस प्रकार का निवेश न सिर्फ इन सब्सिडियों के प्रयोग की अक्षमता को दिखाता है बल्कि इससे पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होती है।
- चीन के तर्ज पर भारत को भी सभी लागत सब्सिडियों को समेकित कर देना चाहिए तथा उसके बदले में किसानों प्रत्यक्ष आय सहायता देने चाहिए। इससे भारतीय किसानों में क्षमता, विकास तथा कृषि उत्पादन जैसे क्षेत्र में दुरगामी परिणाम होंगे। किसी देश की घरेलू कृषि से सम्बन्धित कानूनों तथा विदेशी कृषि उत्पादों के आयात से सम्बन्धित कानूनों को उसकी कृषि नीति कहते है जैसे आर्थिक नीति,

औद्योगिक नीति, ऊर्जा नीति (हरित क्रान्ति) नई कृषि नीति है सन् 1966–67 में भारत सरकार ने कई कृषि नीति का ऐलान किया। यह नीति मुख्य रूप से नए किस्म के संकर बीजों प्रसार से सम्बन्धित थी।

- बीज खाद दवा का प्रबन्ध
- बैंक से लोन का प्रबन्ध
- भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दामों पर खरीदी
- सिंचाई के लिये मोटरपम्प, बिजली, डीजल आदि का प्रबन्ध

कृषि उत्पादकता कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें कृषि इनपुट्स जैसे– जमीन, पानी, बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवता, कृषि ऋण एवं फसल बीमा की सुविधा, कृषि उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्यों का आश्वासन और स्टोरेज एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि शामिल है।

2009–10 तक देश की आधी से अधिक श्रम शक्ति (53%) यानी 243 मिलियन लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत थे। इस क्षेत्र से अपनी आजीविका कमाने वाले लोगों में भू–स्वामी, काश्तकार जोकि जमीन के एक टुकड़े में खेती करने और खेत मजदूर जो इन खेतों में मजदूरी करते शामिल है। पिछले 10 वर्षो के दौरान कृषि उत्पादन अस्थिर रहा है इसकी वार्षिक वृद्धि 2010–11 में 86%, 2014–15 में 0.2% और 2015–16 में 0.8% थी। पिछले 10 वर्षो के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया गया है।

कृषि क्षेत्र में देश की लगभग 75% कृषि पर निर्भर है। हालाकि जी.डी.पी. में इसका योगदान 17.5% है। 1950 में जी.डी.पी. में कृषि क्षेत्र का योगदान जहॉ 50% या वही 2015–16 में यह गिरकर 15.4% रह गया।

❖ भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि दर (Agricultural Productivity Growth Rate in India)

टेबलः 2 कृषि खाद्यान्नो के उत्पादन में वृद्धि दर (2005 से 2018–19)

मिलियन टन

फसल	मौसम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18		2018-19	
														चतुर्थ अग्रिम अनुमान	अंतिम अनुमान	लक्ष्य	चतुर्थ अग्रिम अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
चावल	खरीफ	78.27	80.17	82.66	84.91	75.92	80.65	92.78	92.36	91.50	91.39	91.41	96.30	97.50	97.14	99.00	102.13
	रबी	13.52	13.18	14.03	14.27	13.18	15.33	12.52	12.87	15.15	14.09	13.00	13.40	15.41	15.62	15.00	14.29
	कुल	91.79	93.36	96.69	99.18	89.09	95.98	105.30	105.23	106.65	105.48	104.41	109.70	112.91	112.76	114.00	116.42
	रबी	69.35	75.81	78.57	80.68	80.80	86.87	94.88	93.51	95.85	86.53	92.29	98.51	99.70	99.87	102.20	102.19
गेहूं जवार	खरीफ	4.07	3.71	4.11	3.05	2.76	3.44	3.29	2.84	2.39	2.30	1.82	1.96	2.10	2.27	2.10	1.74
	रबी	3.56	3.44	3.81	4.19	3.93	3.56	2.69	2.44	3.15	3.15	2.42	2.60	2.85	2.53	2.80	2.02
	कुल	7.63	7.15	7.93	7.25	6.70	7.00	5.98	5.28	5.54	5.45	4.24	4.57	4.95	4.80	4.90	3.76
	खरीफ	7.68	8.42	9.97	8.89	6.51	10.37	10.28	8.74	9.25	9.18	8.07	9.73	9.13	9.21	9.50	8.61
बाजरा	खरीफ	2.35	1.44	2.15	2.04	1.89	2.19	1.93	1.57	1.98	2.06	1.82	1.39	1.98	1.99	2.30	1.22
रागी	खरीफ	0.47	0.48	0.55	0.44	0.38	0.44	0.45	0.44	0.43	0.39	0.39	0.44	0.44	0.44	0.60	0.37
कदन्न पोषक	खरीफ	14.58	14.05	16.79	14.42	11.54	16.44	15.95	13.59	14.06	13.93	12.10	13.52	13.64	13.91	14.50	11.95
	रबी	3.56	3.44	3.81	4.19	3.93	3.56	2.69	2.44	3.15	3.15	2.42	2.60	2.85	2.53	2.80	2.02
	कुल	18.14	17.50	20.60	18.62	15.47	20.01	18.64	16.03	17.20	17.08	14.52	16.12	16.50	16.44	17.30	13.97
मक्का	खरीफ	12.16	11.56	15.11	14.12	12.29	16.64	16.49	16.20	17.15	17.01	16.05	18.92	20.24	20.12	21.20	19.04
	रबी	2.55	3.54	3.85	5.61	4.43	5.09	5.27	6.05	7.11	7.16	6.51	6.98	8.47	8.63	7.50	8.18
	कुल	14.71	15.10	18.96	19.73	16.72	21.73	21.76	22.26	24.26	24.17	22.57	25.90	28.72	28.75	28.70	27.23

जौ	रबी	1.22	1.33	1.20	1.69	1.35	1.66	1.62	1.75	1.83	1.61	1.44	1.75	1.77	1.78	2.10	1.75
पोषक/मोटे अनाज	खरीफ	26.74	25.61	31.89	28.54	23.83	33.08	32.44	29.79	31.20	30.94	28.15	32.44	33.89	34.03	35.70	30.99
	रबी	jch	8.31	8.86	11.49	9.72	10.32	9.58	10.24	12.09	11.92	10.37	11.33	13.10	12.94	12.40	11.96
	कुल	34.07	33.92	40.75	40.04	33.55	43.40	42.01	40.04	43.30	42.86	38.52	43.77	46.99	46.97	48.10	42.95
अनाज	खरीफ	105.01	105.78	114.55	113.45	99.75	113.73	125.22	122.15	122.70	122.34	119.56	128.74	131.38	131.16	134.70	133.12
	रबी	90.21	97.30	101.46	106.45	103.70	112.52	116.98	116.63	123.09	112.53	115.66	123.24	128.21	128.44	129.60	128.43
	कुल	195.22	203.08	216.01	219.90	203.45	226.25	242.20	238.78	245.79	234.87	235.22	251.98	259.59	259.60	264.30	261.55
तूर	खरीफ	2.74	2.31	3.08	2.27	2.46	2.86	2.65	3.02	3.17	2.81	2.56	4.87	4.25	4.29	4.50	3.59
चना	रबी	5.60	6.33	5.75	7.06	7.48	8.22	7.70	8.83	9.53	7.33	7.06	9.38	11.23	11.38	11.50	10.13
उड़द	खरीफ	0.90	0.94	1.12	0.84	0.81	1.40	1.23	1.50	1.15	1.28	1.25	2.18	2.84	2.75	2.80	2.56
	रबी	0.35	0.50	0.34	0.33	0.42	0.36	0.53	0.47	0.55	0.68	0.70	0.66	0.73	0.74	0.80	0.70
	कुल	1.25	1.44	1.46	1.17	1.24	1.76	1.77	1.97	1.70	1.96	1.95	2.83	3.56	3.49	3.60	3.26
मूंग	खरीफ	0.69	0.84	1.25	0.78	0.44	1.53	1.24	0.79	0.96	0.87	1.00	1.64	1.44	1.43	1.55	1.84
	रबी	0.26	0.28	0.27	0.26	0.25	0.27	0.40	0.40	0.65	0.64	0.59	0.52	0.57	0.59	0.70	0.51
	कुल	0.95	1.12	1.52	1.03	0.69	1.80	1.63	1.19	1.61	1.50	1.59	2.17	2.01	2.02	2.25	2.35
मसूर	रबी	0.95	0.91	0.81	0.95	1.03	0.94	1.06	1.13	1.02	1.04	0.98	1.22	1.61	1.62	*	1.56
अन्य खरीफ दलहन	खरीफ	0.54	0.70	0.96	0.80	0.49	1.33	0.93	0.61	0.71	0.78	0.72	0.89	0.82	0.83	1.00	0.61
अन्य रबी दलहन	रबी	1.36	1.37	1.19	1.28	1.28	1.33	1.34	1.59	1.52	1.74	1.47	1.77	1.76	1.78	3.10	1.90
कुल दलहन	खरीफ	4.86	4.80	6.40	4.69	4.20	7.12	6.06	5.92	6.00	5.73	5.53	9.58	9.34	9.31	9.85	8.59
	रबी	8.52	9.40	8.36	9.88	10.46	11.12	11.03	12.43	13.26	11.42	10.79	13.55	15.89	16.11	16.10	14.80
	कुल	13.38	14.20	14.76	14.57	14.66	18.24	17.09	18.34	19.26	17.15	16.32	23.13	25.23	25.42	25.95	23.40
कुल खाद्यान्न	खरीफ	109.87	110.58	120.96	118.14	103.95	120.85	131.27	128.07	128.69	128.07	125.09	138.33	140.73	140.47	144.55	141.71
	रबी	98.73	106.71	109.82	116.33	114.15	123.64	128.01	129.05	136.35	123.96	126.45	136.78	144.10	144.55	145.70	143.24
	कुल	208.60	217.28	230.78	234.47	218.11	244.49	259.29	257.12	265.05	252.02	251.54	275.11	284.83	285.01	290.25	284.95

* अन्य रबी दलहन मे शामिल

स्रोत– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001

भारत में कृषि उत्पादकता 1970–2010 तक औसत पैदावार में वृद्धि

टेबलः 3 कृषि उत्पादकता में औसत वृद्धि (1970–2010)

फसल	औसत कमाई 1970–71 किलो प्रति हेक्टेयर	औसत कमाई 1990–91 किलो प्रति हेक्टेयर	औसत कमाई 2010–11 किलो प्रति हेक्टेयर
Rice	1123	1740	2240
Wheat	1307	2281	2938
Pulses	524	578	689
Oilseeds	579	771	1325
Sugarcane	48322	65395	68596
Tea	1182	1652	1669
Cotton	106	225	510

स्रोत; केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष–1970–71 से 2010–11 में औसत कमाई धीरे–धीरे बढ़ रही है। भारत और चीन चावल की पैदावार पर विश्व रिकार्ड स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे है। चाइना नेशनल हाईब्रिड राइस रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट सेण्टर के युआन लोगपिंग ने 2010 में एक प्लाट में 19 टन प्रति हेक्टेयर चावल की पैदावार का विश्व रिकार्ड बनाया। वर्ष 2011 में इस रिकार्ड को एक भारतीय किसान समत कुमार ने विहार में 22.4 टन प्रति हेक्टेयर के साथ एक प्रदर्शन प्लाट में पीछे छोड़ दिया।

ग्राफ: 1

फसल बीमा के तहत आने वाले किसान दिन प्रतिदिन कृषि उत्पादकता कम होने की उम्मीद है क्योकि उपर्युक्त आंकड़ो से पता चलता है कि फसल बीमा के तहत आने वाले किसान पहले 58.4 मिलियन थे व घटकर 57.6 मिलियन ही रह गये हैं और फसल बीमा वाले क्षेत्र पहले 56.7 मिलियन थे अब घटकर 52.3 मिलियन हो गये हैं।

ग्राफ: 2

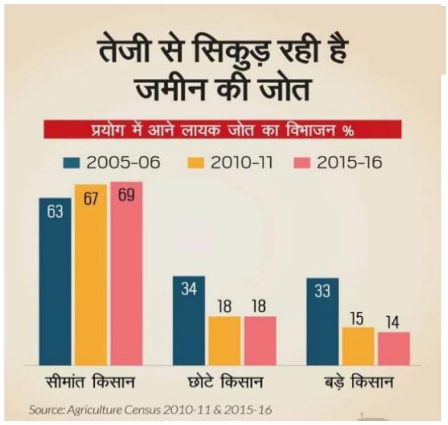

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि 2005–06 में सीमान्त किसान 63 प्रतिशत, छोटे किसान 67प्रतिशत और बड़े किसान 69 प्रतिशत थे और 2010–11 में सीमान्त किसान 34 प्रतिशत, छोटे किसान 18 प्रतिशत व बड़े किसान 18 प्रतिशत है। 2015–16 में सीमान्त किसान 33 प्रतिशत, छोटे किसान 15 प्रतिशत व बड़े किसान 14 प्रतिशत है। अतः इन आंकड़ो से पता चलता है कि सीमान्त किसान, छोटे किसान तथा बड़े किसान दिन प्रतिदिन घट रहे हैं।

ग्राफ: 3

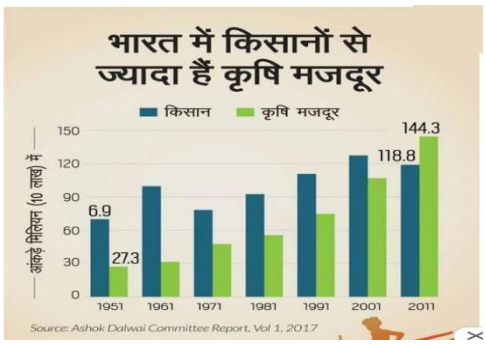

उपर्युक्त आंकड़ो से ज्ञात होता है कि भारत में किसानों से ज्यादा कृषि मजदूरों की संख्या है। 1951 में किसानों की संख्या 6.9 लाख मिलियन है जो 2011 में बढ़कर 118.8 लाख मिलियन है तथा कृषि मजदूर 1951 में 27.3 लाख मिलियन से बढ़कर 144.3 लाख मिलियन है।

❖ राज्य स्तरीय वृद्धि दर (State Level Growth Rate)

1. पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्य उत्पादक राज्य है। चावल उत्पादन में पश्चिमी बंगाल सबसे आगे है। इसके बाद आन्ध्रप्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इसके आलावा यह राज्य जूट–तिल, तम्बाकू और चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में चावल की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 2600 किलोग्राम है। यहा प्रतिवर्ष लगभग 146.05 लाख टन चावल का उत्पादन होता है फल उत्पादन में भी पश्चिम बगांल अग्रणी राज्य है। यहॉ आम, लीची, अननास, अमरूद और सन्तरा सहित कई

फलों का उत्पादन होता है। इसके अलावा यहॉ सब्जियों में फूलगोभी, टमाटर, खीरा, गोभी, और बैगन की खेती होती है। आपको बता दे चावल, जूट और गेहूँ पश्चिम बंगाल में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें है। मसालों में मिर्च, अदरक, लहसुन में भी पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है।

2. उत्तर प्रदेश

सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन के मामले में भी सबसे आगे है। यहॉ बाजरा, चावल, गन्ना, खाद्यान्न और कई अन्य फसलों की खेती होती है। गेहूँ, उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसके बाद हरियाणा, पंजाव और मध्यप्रदेश का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश में 22.5 मिलियन टन गेहूँ का उत्पादन होता है। यहा की जलवायु गेहूँ उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है इसमें 96 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूँ की खेती की जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में भी पहले स्थान पर है यहॉ गन्ना विश्व स्तर पर सबसे अधिक उत्पादित फसल है। यहॉ प्रति वर्ष– 145.39 मिलियन टन गन्ना उत्पादन होता है।

3. पंजाब

हमारे देश में पंजाब सबसे अधिक उपजाऊ राज्य है यहॉ की जलवायु गेहूँ, गन्ना, चावल, सब्जी और फलों के लिए काफी अनुकूल है। पंजाब को भारत में रोटी की टोकरी कहा जाता है। यहॉ लगभग 95% भूमि पर खेती की जाती है। पंजाब के अधिकांश क्षेत्रों में गेहूँ की खेती होती है। पंजाब भारत का तीसरा सबसे बड़ा कृषि फसल उत्पादक राज्य है। यहॉ की सिंचाई प्रणाली बहुत ही उन्नत है।

4. गुजरात

गुजरात भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला कृषि राज्य है। गुजरात में कृषि ऊर्जा और उद्योग के क्षेत्र में काफी निवेश किया गया है। गुजरात में कपास, मूंगफली, आरण्डी, बाजरा, अरहर, चना, तिल, धान, मक्का और गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कपास का भी उत्पादन है। इसके अलावा मूँगफली उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है।

5. हरियाणा

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा में लगभग 70% लोग कृषि कार्य में लगे हुए है। भारत के हरित क्रांति में हरियाणा की एक महत्वपूर्ण भमिका है। इसमें विशाल सिंचाई प्रणाली है। हरियाणा की प्रमुख फसलों में गन्ना, धान, गेहूँ, सूरजमुखी है। हरियाणा सूरजमुखी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा पशुपालन में भी आगे है।

6. मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन के लिए पाया जाता है। दलहन उत्पादन इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। यह प्रदेश सोयाबीन और लहसुन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में किसानों की आय का मुख्य स्रोत गेहूँ, दाल और मक्का है। यहॉ प्रमुख फसलों में उर्द, सोयाबीन और अरहर है।

मध्य प्रदेश एक बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है यहॉ की जलवायु और मिट्टी विभिन्न फसलों के लिए काफी अनुकूल है। मध्य प्रदेश का कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहॉ की 65% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है।

7. असम

असम एक कृषि आधारित राज्य है। अन्य राज्यों की तुलना में असम कम विकसित राज्यों में आता है। यहॉ की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। असम, चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है इसके बाद

हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और अन्य राज्य है। भारत में सबसे प्रसिद्ध चाय नीलगिरी चाय, दार्जिलिंग चाय, असम चाय और कांगडा चाय यही उत्पादित होता है। भारत में कुल चाय का उत्पादन 52% का हिस्सेदारी करता है।

8. आन्ध्र प्रदेश

आन्ध्रप्रदेश में 62% आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। यहॉ चावल उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यहॉ की प्रमुख फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तम्बाकू, दाल, गन्ना और अन्य फसलें है। इसमें 1.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर बागवानी की जाती है।

9. कर्नाटक

कर्नाटक एक समग्र कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। राज्य की अधिकांश आबादी खेती में लगी हुई है। कर्नाटक की जलवायु खेती के लिए काफी अनुकूल है। कर्नाटक की प्रमुख फसलों में चावल, मक्का, मूंग, दाल, लाल मिर्च, गन्ना, मूँगफली, सोयाबीन, हल्दी और कपास है। इसके अलावा यहॉ सरसों, तिल, जौ, गेहूँ, और मटर की खेती होती है। कनार्टक भारत में शीर्ष राज्यों के अन्तर्गत आता है। कर्नाटक काफी उत्पादन में सबसे आगे है। भारत में कुल उत्पादन का 70% काफी कर्नाटक में होता है। यहॉ प्रतिवर्ष लगभग 222.300 मिट्रिक टन काफी का उत्पादन होता है।

10. छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसलों में चावल, बाजरा और मक्का प्रमुख है। छत्तीसगढ़ में 77% क्षेत्र चावल उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। यहॉ केवल 20% भूमि ही सिंचित क्षेत्र में आती है। यहॉ काजू, अमरूद, चीकू, और आम की खेती होती है। यहां मसाला उत्पादन में भी यह राज्य अग्रणी है। यहॉ अदरक, हल्दी, धनियॉ, मेथी, मिर्चा व लहसुन की मात्रा खूब होती है।

टेबलः 4

अनुबंध – 15.1 (क)

आरकेवीवाई–रफ्तार के अंतर्गत वर्ष 31.03.2019 तक राज्यवार आवंटन, निर्मुक्ति एवं 31.12.2019 तक उपयोगिता

(रूपए करोड़ में)

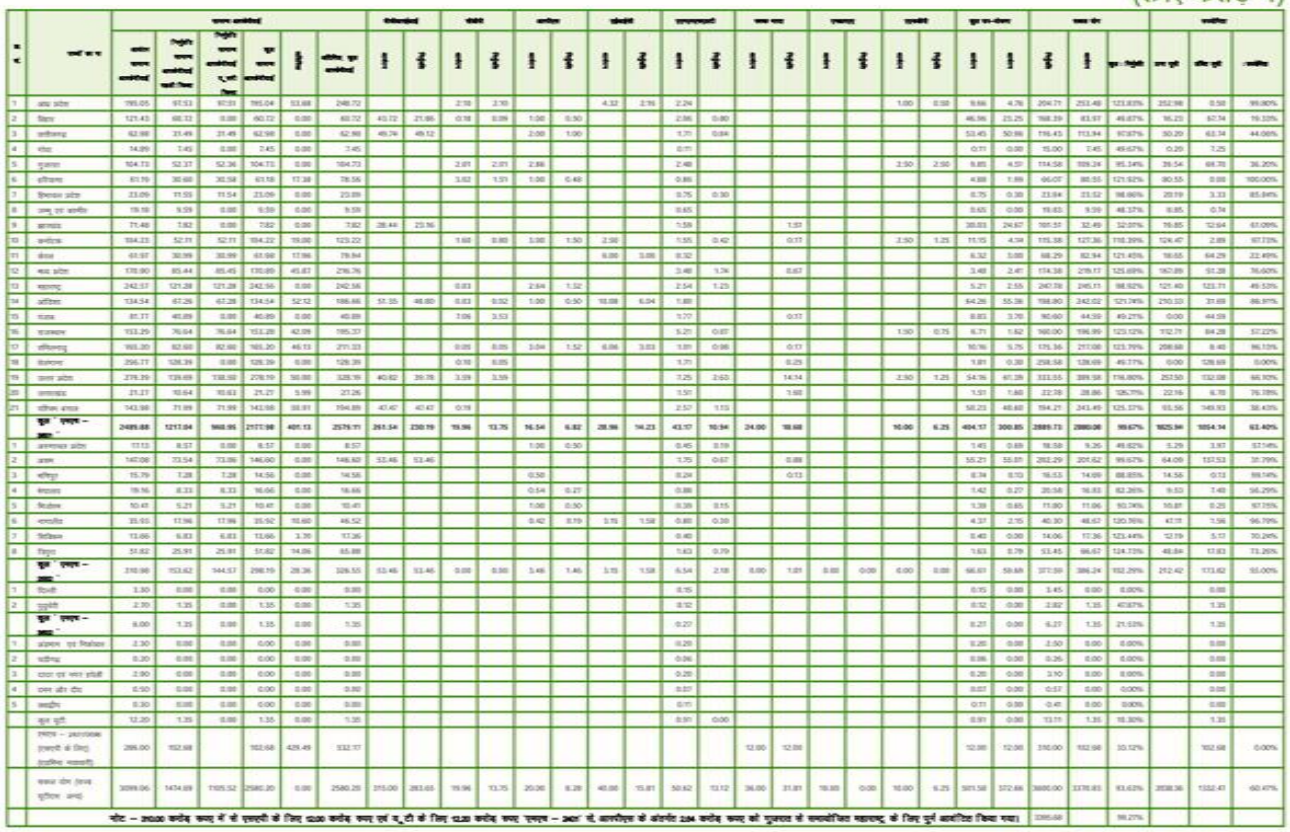

स्रोतः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001

टेबलः 5 कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्रों में जीवीए प्रतिशत

क्षेत्र	वर्ष					
	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का जीवीए	2093612	222753	2496358	670147	2975852	3047187
कुल जीवीए की प्रतिशत	13.2%	17.7%	17.9%	17.2%	16.1%	16.5%

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का जीवीए भारत एवं कृषि सम्बद्ध क्षेत्रों का जीवीए 2014–15 में 2093612 है जो 2019–20 में बढ़कर 3047187 हो गया है जो कुल जीवीए के प्रतिशत का 13.2 प्रतिशत से बढ़कर 2019–20 में 6.5 प्रतिशत हो गया जो कि 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर है। नीचे इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है।

ग्राफः 4

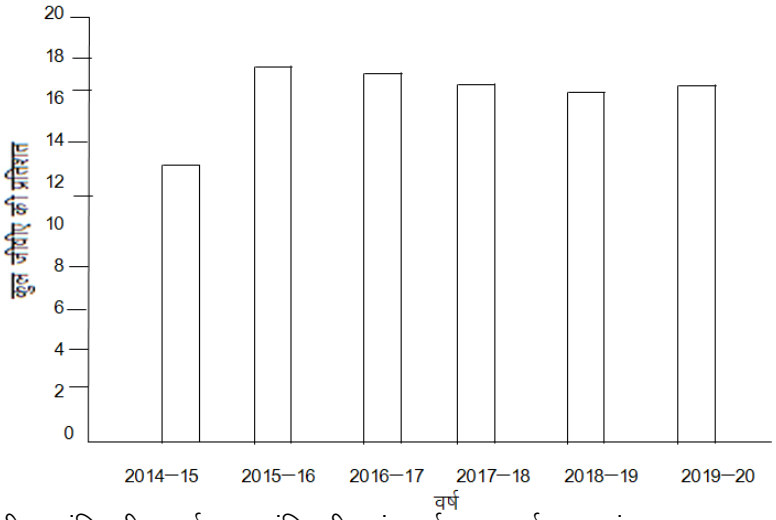

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

❖ **भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलायी जा रही योजनाएं (Schemes being run to increase agricultural productivity in India)**

भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलायी जा रही योजनाएं निम्नलिखित है–

➢ **राष्ट्रीय मृदा–स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबन्धन परियोजना**

राष्ट्रीय मृदा–स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबन्धन परियोजना मृदा परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना तथा किसानों को मृदा उत्पादकता एवं आर्थिक लाभ प्राप्ति हेतु परीक्षण आधारित अनुसार करना है।

➢ **सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन**

सूक्ष्म सिंचाई का राष्ट्रीय मिशन (NMMI) को एक मिशन के रूप में जून 2010 में आरम्भ किया था। NMMI पानी के इस्तेमाल में बेहतर दक्षता फसल की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहनों, दालों एवं मक्का की एकीकृत योजना (NMMI) कपास पर औद्योगिकी मिशन आदि जैसे बड़े सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई गतिविधियों के समावेश को बढ़ावा देना है।

➢ **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है।

- **राष्ट्रीय किसान नीति 2007**
  यह नीति कृषि क्षेत्र को फिर से संशक्त करने और किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई है।

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन**
  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 तक चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन गेहूँ के उत्पादन में 8 मिलियन टन व दलहन के उत्पादन में 2 मिलियन टन की वृद्धि होगी। साथ ही यह अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा।

- **राष्ट्रीय बागवानी मिशन**
  राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना 2006 में चलाई गयी इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करने के साथ–साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना है।

- **आर्टिफिशियल रिचार्ज यू डगवेल्स**
  आर्टिफिशियल रिचार्ज यू डगवेल्स 2008 में चलायी गयी है इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान कुओं को फिर से भरना, भूमि जल स्तर को सुधारना, अभाव के समय में भूमि जल स्तर में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करना और सम्पूर्ण कृषि उत्पादन में सुधार लाना शामिल है।

- **किसान क्रेडिट कार्ड योजना**
  किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत अगस्त 1998 में तत्कालिन किया गया है। (यशवन्त सिंह द्वारा) इसके माध्यम से 1 लाख 60 हजार का लोन दिया जायेगा। इस लोन के माध्यम से देश के किसान अपनी खेती की और अच्छे से देखभाल कर पायेंगे।

- **कृषि संचालन के लिए ऋण योजनाएं** (KCC)
  पीएम किसान क्रेडिट कार्ड को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ दिया गया है। किसान के0सी0सी0 से 4 प्रतिशत ब्याज पर 3 लाख रूपये तक का ऋण ले सकते है।

- **किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना**
  किसानों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण योजना कृषि में निर्धारित योग्यताधारी छात्र दो माह का निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करके 36 प्रतिशत संयुक्त अनुदान (अनुसूचित जाति/जनजाति, पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों/महिलाओं के लिए 44 प्रतिशत) के साथ बैंक ऋण की सहायता से एग्री क्लीनिक/एग्री बिजनेस केन्द्र की स्थापना कर सकता है।

❖ **भारत में कृषि में सुधार के लिए बनायी गयी नीतियां** (Policies made to Improve agriculture in India)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की केन्द्र बिन्दु व भारतीय जीवन की धुरी है आर्थिक जीवन का आधार रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधार शिला कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 52% भाग कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्षेत्रों से ही अपना जीविकोपार्जन कर रही है। अतः यह कहना समीचीन होगा कि कृषि के विकास समृद्धि व उत्नपादकता पर ही देश का विकास व सम्पन्नता निर्भर है।

स्वतंत्रता के पश्चात कृषि को देश की आत्मा के रूप में स्वीकारते हुए एवं खेती को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट किया था कि सब कुछ इन्तजार कर सकता है मगर खेती नहीं, इसी तथ्य का अनुशरण करते हुए भारत सरकार कृषि क्षेत्र को विकसित करने एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु अनेक कार्यक्रमों, नीतियों व योजनाओं का संचालन कर रही है। सरकार ने वर्ष 1960–61 में भूमि सुधार कार्यक्रम का सुत्रपात किया जिससे किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सरकार ने भू–जोतों की अधिकतम सीमा को हकबन्दी जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता पद हो उत्पादन उपज के उचित मूल्य प्राप्त पर भी निर्भर है।

गैरतलब है कि देश के अधिकांश छोटे किसान गरीबी के दुष्चक्र में जकड़े हए है। गरीबी तथा ऋणातस्तता के कारण किसान अपनी उपज कम किमतों पर विचौलियों को बेचने के लिए बाध्य है। इन विचौलियों के जाल से किसानों को मुक्त करवाने तथा विपणन व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सरकार ने नियंत्रित मण्डियों के विस्तार कृषि उपज के श्रेणीकरण व प्रभावीकरण माल गोदामों की व्यवस्था बाजार एवं मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का प्रसारण व सहकारी विपणन व्यवस्था का प्रबन्धन जैसे महत्वपूर्ण कदम है। यह संस्थान कृषि विपणन में विशिष्ट में विशिष्ट शिक्षण–प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सेवाए प्रदान करते हुए कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

इसके अतिरिक्त कृषि उपज की विपणन व्यवस्था को सरल व सुचारू बनाने हेतु गॉवों को निकटवर्ती शहरों से जोड़ने हेतु भारत निर्माण' योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर सर्वाधिक जोर दिया जा रहा है। गैरतलब है कि भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सिंचाई सड़क–जलापूर्ति आवास–विद्युतीकरण व दूरसंचार विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है ताकि कृषि के विकास व उत्पादकता हेतु आधार भूत संरचना को सुदृढ़ किया जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन सब सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का प्रावधान भी रखा गया।

भारतीय कृषि जोखिम भरा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सरकार कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण सम्भाव्य हानि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। इसी प्रकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु 'फसल बीमा योजना' प्रारम्भ की गई, जिसके बाद में व्यापक फसल योजना तथा वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। यही नहीं कृषिगत निर्यातों के विकास हेतु कृषि निर्यात क्षेत्रों को भी स्थापित किया गया है। चिन्ता का विषय यह है कि देश में प्रति वर्ष 21 फसल कीड़े–मकोड़े व बीमारियों के कारण नष्ट हो जाती है जिसको नियंत्रित करने के लिए पौध संरक्षण कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया तथा कीटनाशक दवाइयों के उपयोग पर बल दिया गया। कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण को प्रोत्साहित किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसानों को कम व्याज दर पर ट्रैक्टर, पम्पसेट व मशीनरी आदि खरीदने के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा कृषिगत यंत्रों की किराया क्रय पद्धति व्यवस्था करने हेतु कृषि उद्योग निगमन की स्थापना की गई है।

निष्कर्ष (CONCLUSION)

भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए सरकार कृषि क्षेत्रों में अधिक निवेश करने राज्यों के बजट में कृषि को प्राथमिकता देने हेतु प्रोत्साहित करने नवीन कृषि तकनीक के उपयोग को प्रेरित करने तथा कृषि उत्पादन में आने वाली समस्त बाधाओं का निवारण करने हेतु सतत् प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय किसान आयोग (2004–06) ने देश में कृषि की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु जलवायु के अनुकूल कृषि आर्थिक तकनीकों के इस्तेमाल तथा हरित क्रान्ति से लाभान्वित प्रदेशों में अनाज सरक्षण की व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया है। जिस पर क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। कृषि को समुन्नत बनाने हेतु ग्यारवी पंचवर्षीय योजना में मृदा संरक्षण जल–जल स्रोतों के पुरूद्धार ऋण व आगत आपूर्ति में सुधार पर जो दिया गया है। फसल उत्पादन में मिट्टी की किस्म पोषक तत्व व जलग्रहण क्षमता के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए गॉवों में सचल मिट्टी परिक्षण इकाईयॉ स्थापित की गई।

इसी प्रकार किसानों को कृषि पशुपालन, मत्स्य–पालन आदि से सम्बन्धित सूचनाऍ शीघ्र व समय पर उपलब्ध कराने हेतु ग्राम संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। कृषि में जोखिम अधिक है। अतः इससे किसानों के सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए फसल बीमा योजना को व्यापक व तार्किक बनाते हुए बीमा प्रीमियम दर कृषकों की आय के अनुपात में रख्ना न्याय संगत होगा। इसके साथ विकसित के मुकाबले करने के लिए कृषि को उद्योग देते हुए उसे व्यवहारिक बनाने की कोशिश किया जाना चाहिए। ग्रामीण अधो संरचना विकास को प्राथमिकता देकर कृषि को अधिक प्रतियोगी व लाभप्रद बनाना सम्भव है। ग्रामीण विकास के इस महानिदान में पंचायती राज संस्थाओं व ग्राम सभाओं को भी वृद्धि जिम्मेदारियॉ निभानी होगी।

रिजर्व बैंक का शहरी बैंक विभाग अपने विभिन्न खण्डों के माध्यम से सहाकारी बैंकों की गतिविधियों पर ध्यान रखता है तथा जमा कर्ताओं के हित एवं जनहित को ध्यान में रखते हैं सहकारी बैंकों के नियमन का कार्य करा है।

परिचर्चा (DISCUSSION)

कृषि वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हर साल कृषि उत्पादकता के वृद्धि दर में कमियां पायी गयी है। इस शोध में जमीनी स्तर पर देखे तो कृषि क्षेत्र में रोजगार, उत्पादकता एवं कृषि क्षेत्र में काम करने की लोगों की जो इच्छाएं घटती जा रही है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ने की वजह से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने वाले जो साधन है उनका कीमत बढ़ती जा रही है। इसके वजह से जो ग्रामीण गरीब किसान है वह उन साधनों को धन के अभाव के कारण खरीद नहीं पा रहे है। जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र में लोगों का रूझान और कृषि उत्पादकता दोनो कम हो रही है और जैसे खाद्य, यूरिया, पोटास कृषि यंत्रो आदि की कीमत में वृद्धि होना साथ ही साथ सिंचाई साधनों का अभाव जैसे समय से नहरों में पानी का न आना और असमय वर्षा होना, प्राकृतिक उत्पादन आदि का होना ये मूल कारण है।

हालांकि भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी कृषि स्कीम एवं नितियां समय–समय पर लायी जाती रही है ताकि किसानों को आसान तरीके से कृषि ऋण मिल सके, उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके और समय–समय पर ऋण माफी करना ये सरकार द्वारा किये गये कुछ कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण योजनाएं है और इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के0सी0सी0 1998) का महत्वपूर्ण योगदान (जो किसानों को कृषि से सम्बन्धित ऋण प्रदान करता है) फिर भी सरकार को किसानों के कृषि को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर नयी नीतियां बनाने की जरूरत है और इसको जमीनी स्तर पर अनुशासनिक रूप से लागू करने की जरूरत है।

सुझाव (RECOMMENDATIONS)

प्रो0 माल्थन ने अपने बुक Theory of Population (1798) में खाद्यान्न संकट के सन्दर्भ में कहा था कि किसी देश की जनसंख्या ज्यामितीय तरीके से (2,4,6,8,10) बढ़ती है जबकि खाद्यान्न अंकगणितीय दर से बढ़ती है (1,2,3,4,5) और इसकी वजह से जनसंख्या और खाद्यान्न में असंतुलन के कारण भूखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ती है अगर यही स्थिति रही जनसंख्या 25 वर्ष दोगुनी हो जायेगी। इसकी वजह से कृषि पर अधिक से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हो जायेंगे जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव इस प्रकार है–

- सरकार द्वारा भूमि का उचित आवंटन किया जाय।
- कृषि ऋण सम्बन्धित योजनाओं को अनुशासनिक तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जाय।
- उचित सिंचाई सुविधा का विकास किया जाय एवं बाजार विपणन व्यवस्था का विकास किया जाय।
- उन्नत बीजों एवं उर्वरकों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाय।
- किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाय। साथ ही साथ उच्च स्तर की कृषि तकनीकी उपलब्ध करायी जाय। इन सभी साधनों के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है जिसमें सरकार और किसान दोनों में समन्वय स्थापित होना बेहद जरूरी है।

संन्दर्भ (REFERENCES)

[1]. Mathur, A.S., Das, S & Sircar, S. (2006). Status of agriculture in India: Trends and Pospects. Economic and Political Weekly, 5327-5336
[2]. Bhalia, G.S. & Singh, G. (1997) Recent Development in Indian Agriculture: A state level analysis economic and Political Weekly, A2-A18.
[3]. Srinivasan, T.N. (1979) Trends in Agriculture in India, 1949-50-1977-78 economic and Political Weekly, 1283-1294.
[4]. Chand, R. (2005) exploring possibilites of achieving four percentage groeth rate in Indian agriculture.
[5]. Chhatterjee, T. (2017) Spatial Convergence and growth in Indian agriculture 1967-2010. Journal of Quantitative economics 15(1) 121-149.
[6]. Kalirajan, K.P. & Shond, R.T. (1997) souces of output growth in India agriculture Indian Journal of Agricultural Economic 52(4) 693-706.
[7]. Birthal, P.S. Singh, H & Kumar S. (2011) Agriculture Economic growth and regional dispartites in India Journal of International Development 23 (1), 119-131.
[8]. Gadgil, S. & Gadgil, S. (2006) The Indian Mansoon GDP and Agriculture Economic and Political Weekly, 4887-4895.
[9]. Dholakia, R.H., & Dholakia, B.H. (1993). Growth of Total Factor Prodoctivity in Indian Agriculture Indian Economic Review 25-40.
[10]. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मयार्दित वार्षिक प्रतिवेदन 2007–12 मुरैना।
[11]. सांख्यिकी एवं आर्थिक संचालनालय सांख्यिकी पुस्तिका म.प्र. भोपाल।
[12]. आर्थिक– जगत भारत सरकार, नई दिल्ली।
[13]. मध्य प्रदेश संन्देश– मध्य प्रदेश शासन–भोपाल।
[14]. इकोनामिक्स टाइम्स, नई दिल्ली।